

जनसंख्या शिक्षा: आवश्यकता एवं महत्व

प्राप्ति: 26.05.2023
स्वीकृत: 20.06.2023

डॉ० सुमिता शर्मा

प्रभारी एवं एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग
एन०के०बी०एम०जी० (पी०जी०) कॉलेज,
चन्दौसी (सम्भल)
एम०जे०पी० रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
ईमेल: sumitasharma.246@gmail.com

21

सारांश

भारत में जनसंख्या विस्फोट ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आगामी कुछ वर्षों में भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़कर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जायेगा। यह कोई आदर्श स्थिति नहीं होगी इसलिये और भी नहीं क्योंकि चीन के मुकाबले भारत का क्षेत्रफल कम है। भारत के पास दुनिया का केवल 2.4 प्रतिशत भूभाग है लेकिन विश्व की 18 प्रतिशत आबादी यहाँ रहती है और यह किसी से छिपा नहीं है कि संसाधनों का बोझ बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि अनेक समस्याओं को जन्म दे रही है जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, प्रदूषण आदि। इसलिये जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सजग रहना समय की मांग है। उन वर्गों और क्षेत्रों को जनसंख्या नियन्त्रण की महत्ता से परिचित कराना होगा जहाँ इसके प्रति जागरूकता का अभाव है। इसी के साथ जनसंख्या नियोजन के उपायों पर भी प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना होगा। शिक्षित और अनुशासित जनसंख्या ही किसी देश की प्रगति में सहायक बनती है। आज जनसंख्या शिक्षा द्वारा इस बात पर बल दिया जा रहा है कि छात्र-छात्रायें तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न दुष्परिणामों से अवगत हो, उसके कारणों की खोज करें और उसके दूर करने के उपायों पर चिन्तन करके 'जनसंख्या वृद्धि रोको' नारे के द्वारा एक जन-आन्दोलन खड़ा करें जिससे सबका ध्यान इस ज्वलन्त समस्या की ओर आकृष्ट हो सके और सभी इस जन-आन्दोलन में सहभागी बनकर जनसंख्या विभीषिका से संघर्ष कर सके।

मुख्य बिन्दु

जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या नियन्त्रण संसाधन, जनसंख्या शिक्षा।

वर्तमान समय की समस्याओं में जनसंख्या विस्फोट सम्पूर्ण विश्व के लिये एक चुनौती बन गया है ज्ञान, विज्ञान व सुविधाओं को सभी व्यक्तियों तक पहुँचाना बहुत कठिन होता जा रहा है यदि इसी गति से जनसंख्या बढ़ती गई तो आशंका है कि सभी को भोजन, कपड़ा और मकान नहीं मिल पाएगा। स्वास्थ्य, शैक्षिक व अन्य सुविधाओं की तो बात ही अलग है। भारत में जनसंख्या वृद्धि एक गम्भीर समस्या बनी हुई है। विश्व जनसंख्या दिवस के बाद से जनसंख्या नियन्त्रण को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है

उसके संदर्भ में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानि एनएचएफएस-5 की रिपोर्ट का खूब हवाला दिया जा रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रजनन दर में लगातार कमी आ रही है और देश अब प्रतिस्थापन दर को प्राप्त करने वाला है इस रिपोर्ट के आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि भारत को अब जनसंख्या नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है इस मामले में सबसे पहले तो यह समझना होगा कि देश में जनसंख्या के सबसे प्रमाणित आंकड़े 2011 की जनगणना के हैं। इस जनगणना के अनुसार देश में कुल विवाहित महिलाओं की संख्या 33,96,21,277 थी जिनमें से 18,19,74,153 महिलाएँ ऐसी थी जिनके तीन या इससे अधिक बच्चे थे। क्या इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत प्रतिस्थापन दर को प्राप्त करने वाला है? एनएचएफएस-5 की रिपोर्ट को समझने के लिये यह जानना भी आवश्यक है कि यह केवल एक सैंपल सर्वे है इसमें देश के मात्र सात लाख परिवारों का सर्वे किया गया। इस सैंपल साइज में मजहब, क्षेत्र, जाति आदि के आधार पर कुल संख्या के प्रतिशत को भी ध्यान में रखकर सैंपल एकत्र नहीं किया गया। स्पष्ट है कि ऐसे सैंपल में सभी का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया। यूएन पापुलेशन प्रस्पेक्ट्स की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2027 में चीन की जनसंख्या को पार करना था। अब यूएन को ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2023 में ही भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी।

2001 में हुई जनगणना में भारत की जनसंख्या लगभग 102 करोड़ बताई गई थी जबकि वर्तमान में यूएन के आँकड़े के अनुसार भारत की जनसंख्या 142 करोड़ बताई जा रही है। 2021 में होने वाली जनगणना को कोविड-19 के कारण विलंब से प्रारम्भ किया गया। इसकी रिपोर्ट आने पर स्थिति और अधिक स्पष्ट हो जायेगी। वर्तमान में उपलब्ध सरकारी आँकड़ों को देखने से पता चलता है कि 2000 से 2021 तक भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 42 करोड़ की वृद्धि हुई अर्थात् गत 21 वर्षों में लगभग दो करोड़ प्रतिवर्ष की वृद्धि। अतः भारत में जनसंख्या विस्फोट ने विकराल रूप धारण कर लिया है। अतः इस पर नियंत्रण करने के लिए दो उपायों का प्रयोग किया जा रहा है। पहला परिवार नियोजन और दूसरा जनसंख्या शिक्षा। भारत सरकार ने कोलम्बिया विश्वविद्यालय प्रोफेसर वेलेंड के कार्य से प्रभावित होकर जनसंख्या-शिक्षा की योजना को लागू किया। भारत सरकार के आदेशानुसार 'परिवार नियोजन संघ' ने 7 तथा 8 मार्च, 1969 को बम्बई में एक सेमिनार का आयोजन किया और उसमें जनसंख्या-शिक्षा के प्रसार को प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव को शिक्षाविदों तथा सरकार का समर्थन मिला और उसी समय से इसको व्यवहारिक रूप प्रदान किये जाने का सतत् प्रयास किया जा रहा है।

हमारे देश में जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय कार्यक्रम 1980 में राष्ट्रीय जन-शिक्षा परियोजना (NPEP) के रूप में प्रारम्भ हुआ। इस परियोजना का उद्देश्य था स्कूल शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा को नियमित रूप से शामिल किया जाये। यह योजना देश में 'संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष' और यूनेस्को के सहयोग से प्रारम्भ की गई थी। जनसंख्या शिक्षा को अनौपचारिक, प्रौढ़ शिक्षा तथा विश्वविद्यालय शिक्षा से सम्बन्धित किया गया है। जनसंख्या शिक्षा पर पाठ्य पुस्तकों और पाठों का निर्माण एन0सी0ई0आर0टी0 करती है। "फेमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इण्डिया" और "फेडरेशन ऑफ एजुकेशन एसोसिएशन" जैसी संस्थायें जनसंख्या शिक्षा के प्रसार में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य परिवार-नियोजन तथा संख्या वृद्धि के नियंत्रण के विषय

में व्यक्तियों को सजग बनाना है। साथ ही उसका राष्ट्र विकास से सम्बन्ध स्थापित करके राष्ट्र उन्नति के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए लोगों में समझदारी उत्पन्न करना है। यह यौन-शिक्षा या पारिवारिक जीवन की शिक्षा न होकर "जनसंख्या-जागृति" (Population Awareness) है।

भारतीय संसद संघ के द्वितीय अधिवेशन के उद्घाटन भाषण में दिनांक 13.05.1985 को श्री राजीव गांधी ने कहा कि "जन्म दर पर नियंत्रण का प्रश्न केवल परिवार नियोजन का ही प्रश्न नहीं है वरन् समाज के पुनर्निर्माण का प्रश्न भी है। जन्म दर को नियन्त्रित करने के लिए दवाब या बल का प्रयोग नहीं करना है। वास्तविक परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से तथा सामाजिक सुधार के माध्यम से होगा।" जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से छात्र-छात्राओं में जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं के प्रति चेतना को जागृत किया जाता है। उनमें दृष्टिकोण और विचारों में इस प्रकार का परिवर्तन लाया जाता है कि वह जनसंख्या को सीमित करने के लिए स्वयं चिन्तनशील हो जाये। यह एक शैक्षिक प्रयास है इसके अन्तर्गत यौन शिक्षा, पारिवारिक जीवन की सुरक्षा की शिक्षा, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य पोषण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर जनसंख्या का प्रभाव, पर्यावरण तथ्यों का ज्ञान आदि को सम्मिलित किया गया है। जनसंख्या शिक्षा को विद्वानों ने अपने-अपने मतानुसार परिभाषित किया है परन्तु सबका विचार एक ही दृष्टिकोण पर केन्द्रित है- 'छोटा परिवार सुखी परिवार'। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार "जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों, विशेषकर छात्र-छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश-प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति जनांकिकी के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक सम्बन्ध, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर प्रभाव आदि का बोध कराया जा सकेगा। साथ ही जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं और जनसाधारण में जीवन स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में भी जागरूक कराया जा सकेगा।"

जनसंख्या शिक्षा के विशेषज्ञों का मानना है कि भारतवर्ष जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से गुजर रहा है। समय रहते दूरदर्शिता के साथ इसका समाधान नहीं किया गया तो निश्चय ही भारतवर्ष का भविष्य अन्धकार मय हो जायेगा। अतः इस स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए आवश्यक हो गया है कि जनसंख्या शिक्षा प्रत्येक नागरिक को दी जाये चाहे वह व्यक्ति किसी भी आयु स्तर का है अर्थात् यह शिक्षा बालकों किशोरों, व्यस्कों, प्रौढ़ों वृद्धों स्त्री, पुरुष, विवाहित, अविवाहित शहरी व ग्रामीण सभी को दी जाये। इस जन आन्दोलन को सफल बनाने हेतु सरकारी प्रयासों के साथ-साथ अन्य साधनों, युवा संगठनों, महिला मंडलों तथा अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं को भी आगे आना होगा।

यदि हम भारत की जन्म दर और मृत्यु दर देखें तो पता चलता है कि देश में प्रतिवर्ष लगभग 2.5 करोड़ बच्चों का जन्म होता है और लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु होती है, इस हिसाब से देश में प्रतिवर्ष लगभग 1.5 करोड़ या इससे भी अधिक की जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिसके कारण विकास की योजनाओं का लाभ सभी व्यक्तियों तक नहीं पहुँच रहा है। यह मानकर चलना चाहिए कि मृत्यु दर का प्रतिशत अभी और घटेगा अतः अब जन्म दर को रोकने या कम करने का प्रयास करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों को प्रस्तुत करके उसके दुष्परिणामों की व्याख्या करके छात्रों के मस्तिष्क में ऐसी चेतना प्रस्तुत करनी है जिससे वे भावी जीवन में सन्तानोत्पत्ति को सीमित करें और खुशहाल दाम्पत्य जीवन व्यतीत करें। लोकतांत्रिक प्रणाली वाले भारत में कठोर कानून नहीं लाये जा सकते। अतः

शिक्षा ही उसका सर्वोत्तम साधन है। जनसंख्या शिक्षा के अन्तर्गत पर्यावरण और वातावरण की स्वच्छता, सफाई सम्बन्धी ज्ञान भी सम्मिलित है। दूषित पर्यावरण और वातावरण में मानव का स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं है उसमें शरीर व मानसिक विकास की गति भी अवरूद्ध होती है। पेड़ पौधे भी व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। यह सर्वविदित है कि मानव सुख की वृद्धि में वन-सम्पदा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं रोटी, कपड़ा और मकान। इनकी पूर्ति हेतु सीमित भूमि में अधिक रसायनिक खाद, दवाईयाँ उत्पादन बढ़ाने के लिये डाली जा रही है जिससे भूमि का शरण हो रहा है। कपड़ा आपूर्ति हेतु बड़ी संख्या में फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं। मकान बनाने के लिये ईंट के भट्टों की संख्या बढ़ रही है जिसके कारण ध्वनि जल व वायु प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है जो मानव जीवन के लिये घातक है। अतः प्रदूषण का मूल कारण भी जनसंख्या वृद्धि ही है अतः इसको जनसंख्या शिक्षा द्वारा ही रोका जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि का सीधा प्रभाव देश के सामाजिक और आर्थिक विकास पर पड़ता है सारा संसाधन जनता के पेट भरने में लग जाता है जिससे अन्य प्रगति नहीं हो पाती यदि परिवार खुशहाल रहता है तो समाज का विकास अच्छा होता है और उससे राष्ट्र का। बालक राष्ट्र का भविष्य है। अतः बालक के स्वस्थ होने के लिये माँ का भी स्वस्थ होना अत्यन्त आवश्यक है, इस हेतु मातृ एवं शिशु कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों की जानकारी जनसंख्या शिक्षा से प्राप्त होती है। इन कार्यक्रमों से प्रसव के पूर्व, प्रसव के समय और प्रसव के उपरान्त माँ की देखभाल, सुरक्षित प्रसव, प्रसव के उपरान्त माँ व शिशु की देखभाल, शिशु के आहार एवं स्तनपान सम्बन्धी ज्ञान, शिशुओं को गम्भीर बीमारियों से प्रतिरक्षण हेतु टीके सम्बन्धी जानकारी, नवजात शिशुओं के जन्म से लगभग 4 वर्ष की अवस्था तक उन्हें रोगों से बचाये रखने सम्बन्धी ज्ञान, माँ व शिशु हेतु पौष्टिक आहार सम्बन्धी आदि जानकारी प्राप्त होती है।

देश में चले रहे परिवार नियोजन के कार्यक्रम असफल हो रहे हैं क्योंकि लोगों में आंतरिक प्रेरणा का अभाव पाया जा रहा है। किसी दम्पति को परिवार नियोजन के लिये तुरंत एक घण्टे या दो घण्टे में अभिप्रेरित करना कठिन होता है वहीं दूसरे दम्पति इसे तुरन्त अपना रहे हैं जिनका ज्यादा बच्चे होने का अनुभव खराब है या जो भुक्तभोगी हैं। ऐसे लोगों की संख्या कम है क्योंकि अधिक बच्चों का प्रभाव तुरन्त नहीं पड़ता जब बच्चे बड़े होते हैं और उनकी समस्याएँ बढ़ती हैं तब उन्हें अनुभव होता है। जिसका तब कोई लाभ नहीं। अतः जनसंख्या शिक्षा इसलिये आवश्यक है क्योंकि विद्यार्थी को दम्पति बनने से पहले ही इसका अनुभव करा दिया जाता है जिससे वे इस विषय में जागृत रहते हैं और किसी भी कार्यक्रम को जो परिवार वृद्धि रोकता है उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। जनसंख्या शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कोठारी आयोग ने कहा है "विस्तृत रूप से जनसंख्या शिक्षा युवा पीढ़ी के समकालीन जीवन की वास्तविकताओं को समझते हुए प्रभावी नागरिक बनाने का एक तरीका है।"

सर्वेक्षणों से यह भी पता चलता है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या अधिक है वहीं यह भी सच्चाई नकारी नहीं जा सकती कि इसके अन्तर्गत वे परिवार अधिक आते हैं जिन परिवारों में बच्चों की संख्या अधिक है। एक मजदूरी करके जीवन यापन करने व्यक्ति के छः से अधिक बच्चे पा गये हैं क्या इसे ईश्वरीय वरदान मानकर स्वीकार कर लिया जाये?

तो यह भी तर्क है कि ईश्वर प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने की स्वीकृति किसी को भी नहीं देता। जमीन तथा संसाधनों में जब वृद्धि नहीं होती है तो जनसंख्या वृद्धि व्यक्ति को गरीबी की तरफ ले जाती है। भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की लेकिन उस विकास का लाभ अभी तक जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं पहुँच सका है। अतः जनसंख्या शिक्षा द्वारा स्वस्थ दृष्टिकोण पैदा करने की आवश्यकता है।

जनसंख्या शिक्षा एक वृहत जीवन मूल्य और राष्ट्रीय मूल्य है। वर्तमान समय में कोई भी समझदार व्यक्ति जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व की उपेक्षा नहीं कर सकता। यह एक महत्वपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा युवा छात्र व छात्रायें अपनी उन्नति के लिये संकल्प लेने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। जनसंख्या शिक्षा प्रत्येक मनुष्य की भोजन, आवास, वस्त्र, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा प्राप्ति के अवसर, सुखी पारिवारिक जीवन एवं उच्च जीवन स्तर सम्बन्धी समस्याओं का हल प्रस्तुत करती है। यह जीवन में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं पर अपने महत्वपूर्ण प्रभाव को स्पष्ट करती है। जनसंख्या शिक्षा में परिवार समाज तथा राष्ट्र से सम्बन्धित समस्त बुनियादी मूल्यों की जानकारी सम्मिलित रहती है। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि जनसंख्या शिक्षा हमारी सम्पूर्ण समृद्धि शिक्षा व्यवस्थाओं वास्तविक एवं सार्थक बनाती है।

संदर्भ

1. टण्डन, डॉ० उमा., गुप्ता, डॉ० अरुणा. उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक।
2. गौतम, प्रो० एस०एन०. भारतीय शिक्षा का विकास एवं. डॉ० मालती सारस्वत एवं सामयिक समस्यायें।
3. श्रीवास्तव, डॉ० डी०एन., वर्मा, डॉ० प्रीति. बाल मनोविज्ञान: बाल विकास।
4. सुखिया, एस०पी०. विद्यालय प्रशासन एवं संगठन।
5. पाण्डेय, डॉ० राम शक्ल. उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक।
6. पाठक, पी०डी०. भारतीय शिक्षक और उसकी समस्यायें।
7. समाचार पत्र. दैनिक जागरण।